राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2857/2016

सुनीता कुमारी उर्फ सुनीता देवी पत्नी श्री नारायण राम और पत्नी श्री छोटू राम, उम्र 30 वर्ष, निवासी गांव व पोस्ट बांसा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर। ---याचिकाकर्ता

बनाम

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से राजस्थान राज्य।

2. महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, डीडवाना, जिला नागौर।

3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, मोलासर, जिला नागौर।

4. सरपंच, ग्राम पंचायत, बांसा, पंचायत समिति मोलासर, जिला नागौर।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री नरेश सिंह

श्री राकेश अरोड़ा

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री अनिल कुमार बिस्सा

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश

14/05/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत प्रतिवादियों द्वारा उसके चयन के बावजूद उसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्त न करने के खिलाफ है।

2. संक्षेप में, याचिका में बताए गए मामले के तथ्य इस प्रकार हैं: प्रतिवादी संख्या 2 (महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी) ने प्रतिवादी संख्या 4 (गांव के सरपंच) को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती करने का निर्देश दिया। चयन ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 26.05.2013 (अनुलग्नक 5) के प्रस्ताव के माध्यम से किया जाना था। इसके बाद, ग्राम पंचायत (प्रतिवादी संख्या 4) ने आवेदन आमंत्रित किए और याचिकाकर्ता का चयन दिनांक 20.06.2015 को पारित प्रस्ताव के माध्यम से किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 ने प्रतिवादी संख्या 2 को याचिकाकर्ता के चयन के बारे में दिनांक 20.06.2015 (अनुलग्नक 7) के पत्र के माध्यम से सूचित किया। हालांकि, याचिकाकर्ता को नियुक्त करने के बजाय, प्रतिवादी संख्या 3 (विकास अधिकारी) ने 18.02.2016 को एक पत्र जारी किया, जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के नए चयन के उद्देश्य से ग्राम सभा की बैठक बुलाने का निर्देश दिया गया।

3. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा अपने उत्तर में जो बचाव किया गया है, वह यह है कि ग्राम पंचायत (प्रतिवादी संख्या 4) ने ग्राम सभा की बैठक और याचिकाकर्ता के चयन के बारे में विभाग को सूचित नहीं किया। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने अपने चयन के संबंध में प्रतिवादी संख्या 2 से

संपर्क नहीं किया। इसलिए, विभाग ने प्रतिवादी संख्या 4 को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने संबंधित पक्षों के वकील के तर्कों पर विचार किया है और केस फाइल का अवलोकन किया है।

5. विवाद इस प्रश्न के इर्द-गिर्द घूमता है कि क्या ऐसी स्थिति में, जहाँ केवल एक ही उम्मीदवार विज्ञापित पद के लिए आवेदन करता है, भले ही वह पूरी तरह योग्य और पात्र हो, प्रक्रियागत चूक, यदि कोई हो, चयन प्रक्रिया को अमान्य कर देगी?

6. सामान्यतः, प्रक्रियागत चूक निस्संदेह बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि वे पक्षपात और चयन प्राधिकरण के विवेक का दुरुपयोग कर सकती हैं। हालाँकि, इस मामले में, महिला पर्यवेक्षक की अनुपस्थिति के बावजूद, जिसे चयन प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए था, और सरपंच द्वारा इसे सुधारने में विफलता के बावजूद, प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण याचिकाकर्ता का चयन किया गया होगा। इस आधार पर, सरपंच ने इसे पहचानते हुए, और सुविधा के हित में, महिला पर्यवेक्षक की उपलब्धता की प्रतीक्षा किए बिना, याचिकाकर्ता की पात्रता, योग्यता और पद के लिए उपयुक्तता के आधार पर उसका चयन किया।

7. मुझे उपरोक्त निर्णय में कोई कानूनी दोष नहीं दिखता, और इस प्रकार, प्रतिवादियों द्वारा अपनाए गए अत्यधिक सतर्क दृष्टिकोण को, जैसा कि सुनवाई के दौरान उनके बचाव और तर्कों से स्पष्ट है, अस्वीकार किया जाना चाहिए।

8. मामले का एक और पहलू है, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक ऐसा पद है, जो सरकार के साथ किसी भी तरह का नियमित रोजगार नहीं है, बल्कि स्वैच्छिक सेवा की प्रकृति का है, जिसके

लिए प्रति माह केवल मामूली मानदेय का भुगतान किया जाता है। इसलिए, यह स्वाभाविक है कि वे ऐसे पद के लिए आवेदन करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके अलावा, जैसा कि पहले ही देखा गया है, यह ऐसा मामला भी नहीं है, जहां याचिकाकर्ता में योग्यता या उपयुक्तता की कमी पाई गई हो।

9. मैं यह भी जोड़ना चाहूंगा कि मैं याचिका में दिए गए आधारों और याचिकाकर्ता के वकील के तर्कों से सहमत हूं, जो स्थिति के मेरे आकलन के अनुरूप हैं। प्रतिवादियों ने बहुत अधिक पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है।

10. परिणामस्वरूप, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

11. विदा लेने से पहले, यह भी ध्यान रखना उचित होगा कि सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्न पर, यह पता चला कि एक ओर, प्रतिवादियों ने सफल होने के बाद याचिकाकर्ता की नियुक्ति को रद्द करने के लिए कभी कदम नहीं उठाया, लेकिन फिर भी उन्होंने एक नया विज्ञापन जारी किया, जिसे वैसे भी, इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के तहत रोक दिया गया था। तदनुसार, उक्त विज्ञापन भी समय बीतने के कारण निष्फल हो गया है। यहां तक कि यदि प्रतिवादी उक्त विज्ञापन के अनुसार आगे बढ़ते भी हैं, तो उन्हें एक नया विज्ञापन प्रकाशित करना होगा।

12. संपूर्ण स्थिति में, यह अधिक उचित माना जाता है कि याचिकाकर्ता का चयन, जिसे किसी प्रशासनिक आदेश द्वारा रद्द नहीं किया गया है, बरकरार रखा जाता है और याचिकाकर्ता को संबंधित पद पर शामिल होने की अनुमति दी जाती है।

13. तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि जिस अवधि के लिए याचिकाकर्ता सेवा से बाहर रही, वह "काम नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धांत पर किसी भी वित्तीय लाभ की हकदार नहीं है। 14. नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए आवश्यक कार्यवाही याचिकाकर्ता द्वारा तत्काल आदेश की वेब प्रति के साथ

सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने के 30 दिनों की अवधि के भीतर की जानी चाहिए।

(अरुण मोंगा), जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।